



मनरेगा योजना

प्रलम्बिस् के लयिः

[महातमा गांधी राषट्रीय गुरामीण रोजगार गारंटी योजना \(MGNREGS\)](#), [कोवडि-19](#), आवधकि श्रम बल सरवेक्षण (PLFS)

मेन्स के लयिः

मनरेगा योजना, सरकारी नीतयिँ और हसतकषेप, वकिस से संबंधति मुददे ।

[सुरोतः इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चरचा में क्योँ?

[महातमा गांधी राषट्रीय गुरामीण रोजगार गारंटी योजना \(MGNREGS\)](#) में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो चालू वत्तितीय वर्ष 2023-24 में एक ऐतहासकि वृद्धि है ।

मनरेगा (MGNREGA) में महिलाओं की भागीदारी के रुझान क्या हैं?

- **महिला भागीदारी रुझानः**
 - पछिले दशक में महिलाओं की भागीदारी में क्रमकि वृद्धि हुई है, जिसका प्रतशित वर्ष 2020-21 में [कोवडि-19](#) के प्रकोप के दौरान 53.19% से बढ़कर वर्तमान 59.25% हो गया है ।
 - केरल, तमलिनाडु, पुडुचेरी और गोवा जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी की दर उल्लेखनीय रूप से उच्च है, जो 70% से अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्य लगभग 40% या उससे कम हैं ।
 - ऐतहासकि असमानताओं के बावजूद, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों ने चालू वत्तितीय वर्ष में महिलाओं की भागीदारी दरों में वृद्धिशील प्रतशित के कारण हाल ही में सुधार दिखाया है ।
- **गुरामीण श्रम बल के रुझानः**
 - MGNREGS से परे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा [आवधकि श्रम बल सरवेक्षण \(PLFS\)](#) गुरामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में परयाप्त वृद्धि दिखाता है ।
 - उल्लेखनीय आँकड़े बताते हैं कि गुरामीण महिला LFPR में सत्र 2017-18 में 18.2% से बढ़कर सत्र 2022-23 में 30.5% हो गई है, साथ ही इसी अवधि के दौरान महिला बेरोजगारी दर में 3.8% से 1.8% की गरिवट आई है ।

MGNREGA योजना क्या है?

- **परचियः**
 - MGNREGA [गुरामीण वकिस मंत्रालय](#) द्वारा वर्ष 2005 में शुरू कयि गए वशिव के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है ।
 - यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनकि कार्यों से संबंधति अकुशल शारीरकि कार्य करने के इच्छुक कसिँ भी गुरामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वत्तितीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है ।
 - **सक्रयि करमचारीः** 14.32 करोड़ (सत्र 2023-24)
- **प्रमुख वशिषताएँः**
 - **MGNREGA के डजिाइन की आधारशला इसकी कानूनी गारंटी है**, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी गुरामीण वयस्क कार्य के लयि अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर कार्य मलिना चाहयि ।
 - यदयिह प्रतबिद्धता पूरी नहीं होती है, तो "बेरोजगारी भत्ता" प्रदान कयिा जाना चाहयि ।
 - इसके लयि आवश्यक है कि महिलाओं को इस तरह से प्राथमकिता दी जाए कि कम से कम एक तहिाई महिलाएँ लाभार्थी हों जनिहोंने पंजीकरण कराकर काम के लयि अनुरोध कयिा हो ।
 - MGNREGA की धारा 17 में मनरेगा के तहत नषिपादति सभी कार्यों का सामाजकि लेखा-परीक्षण अनविर्य है ।

- **क्रियान्वति संस्था:**
 - भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) राज्य सरकारों के साथ मलिकर इस योजना के संपूर्ण क्रियान्वयन की नगिरानी कर रहा है।
- **उद्देश्य:**
 - यह अधिनियम ग्रामीण लोगों की **करय शकत** में सुधार लाने के उद्देश्य से पेश किया गया था, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अर्ध या अकुशल कार्य प्रदान करना है।
 - यह देश में अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास करता है।
- **2022-23 की उपलब्धियाँ:**
 - इससे देशभर में लगभग 11.37 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है।
 - इसमें से 289.24 करोड़ व्यक्त-दिविस रोजगार उत्पन्न हुआ है, जिसमें:
 - **56.19% महिलाएँ**
 - **19.75% अनुसूचित जाति (SC)**
 - **17.47% अनुसूचित जनजाति (ST)**

योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **धन वितरण में वलिंब और अपर्याप्तता:**
 - अधिकांश राज्य मनरेगा द्वारा अनविरय 15 दिनों के भीतर मज़दूरी का भुगतान करने में वफिल रहे हैं। इसके अलावा, मज़दूरी के भुगतान में देरी के लिये श्रमकों को मुआवज़ा नहीं दिया जाता है।
 - इसने योजना को आपूर्त-आधारति कार्यक्रम में बदल दिया है और इसके बाद, श्रमकों ने इसके तहत काम करने में रुचि लेना बंद कर दिया है।
 - वतित मंत्रालय की स्वीकारोक्ति सहित अब तक पर्याप्त सबूत हैं कवितन भुगतान में देरी अपर्याप्त धन का परिणाम है।
- **जाति आधारति अलगाव:**
 - जाति के आधार पर वलिंब में महत्त्वपूर्ण भिन्नताएँ थीं। **अनुसूचित जाति** के श्रमकों को 46% और **अनुसूचित जनजाति** के श्रमकों के लिये 37% भुगतान अनविरय सात दिनों की अवधि में पूरा किया गया था, जबकि यह गैर-ST/SC श्रमकों के लिये नरिशानक (26%) था।
 - जाति-आधारति अलगाव का नकारात्मक प्रभाव मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे नरिधन राज्यों में वशिष तौर पर महसूस किया गया।
- **PRI की अपरभावी भूमिका:**
 - बहुत कम स्वायत्तता के कारण **पंचायती राज संस्थान (PRI)** इस अधिनियम को परभावी और कुशल तरीके से लागू करने में सक्षम नहीं है।
- **बड़ी संख्या में अपूर्ण कार्य:**
 - मनरेगा के तहत कार्यों को पूर्ण करने में देरी हुई है और परयोजनाओं का नरिक्षण अनयिमति रहा है। साथ ही, मनरेगा के तहत कार्य की गुणवत्ता और संपत्ति निर्माण का भी मुद्दा है।
- **जॉब कार्ड का नरिमाण:**
 - फरज़ी जॉब कार्डों की मौजूदगी, फरज़ी नामों को शामिल करना, गायब प्रवषिटियाँ और जॉब कार्ड में प्रवषिटियाँ करने में देरी से संबंधति कई मुद्दे हैं।

मनरेगा के अंतरगत कौन-सी पहल हैं?

- **अमृत सरोवर:** इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक ज़िले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का नरिमाण/नवीनीकरण करना है जो सतही तथा भूमगित दोनों जगह जल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेंगे।
- **'जलदत्' ऐप:** इसे 2-3 चयनति खुले कुओं के माध्यम से वर्ष में दो बार कस्ी ग्राम पंचायत में जल स्तर का मापन करने के लिये सतिंबर 2022 में लॉन्च किया गया था।
- **MGNREGS के लिये लोकपाल:** MGNREGS के कार्यावयन से संबंधति वभिन्न स्रोतों से प्रापत शकियातों की सुचारू रपिर्गति तथा वर्गीकरण के लिये फरवरी 2022 में लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया।

आगे की राह

- पारदर्शी एवं समय पर वेतन भुगतान के लिये डजिटल उपकरणों का लाभ उठाते हुए **राज्यों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को नरितर नधि प्रवाह सुनश्चित करने की आवश्यकता है।**
- **बहषिकरण त्रुटियों** पर ध्यान केंद्रति करना तथा उन कषेत्रों की पहचान करना जहाँ हाशयि पर रहने वाले SC और ST परिवार मनरेगा के लाभों से वंचति हैं।
- वधिानसभाओं, नागरकि समाज तथा श्रमकि संघों के माध्यम से सार्वजनकि भागीदारी को शामिल करते हुए सूचित नरिणयों के लक्षिज्य एवं केंद्रीय रोजगार गारंटी परषिदों को सशकत बनाना।

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधनियिम" से लाभ पाने के पात्र हैं? (2011)

- (A) केवल अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजातके परिवारों के वयस्क सदस्य ।
- (B) गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों के वयस्क सदस्य ।
- (C) सभी पछिड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य ।
- (D) कसिी भी घर के वयस्क सदस्य ।

उत्तर: (D)

व्याख्या:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee- MGNREGA), जो वशिव का सबसे बड़ा रोज़गार गारंटी कार्यक्रम है, को वर्ष 2005 में अधनियिमति कयिा गया था, जसिका प्राथमकि उद्देश्य प्रतविरष न्यूनतम 100 दनिों के रोज़गार की गारंटी देना था, जसिके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरकि कार्य करने के लयि सवेच्छा से कार्य करते हैं ।
- इसका उद्देश्य कयि गए 'कार्यों' (परयिोजनाओं) के माध्यम से नरिधनता के कारणों को संबोधति करना और सतत् विकास सुनश्चिति करना है । पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को इन कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमकिा देकर वकिेंद्रीकरण की प्रक्रयिा को मज़बूत करने पर ज़ोर दयिा जा रहा है ।

अतः वकिल्प D सही उत्तर है ।

